सर्किट हाउस में ओडीओपी की बैठक में एमएसएमई राज्य मंत्री और प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन, लेदर पार्क की भी दमदार पैरवी होगी

जूता मंडी होगी आबाद, लैम्को होगा शुरू

आगरा | वरिष्ठ संवाददाता

शाहगंज में पचकुइयां के पास बदहाल चल रही जूता मंडी (जूता प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र) को जल्द ही पूरी तरह से आबाद किया जाएगा। इसके लिए दुकानों की कीमतें 5000 वर्गफीट से कम कर 1000 रुपये के आसपास लाई जाएंगी। यही नहीं 19 साल से बंद चल रहे यूपी लैदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन (लैम्को) को फिर से खोला जाएगा। फतेहपुर सीकरी रोड पर बंद पड़े मेगा लेदर पार्क के प्रोजेक्ट की भी दमदार पैरवी होगी।

देश की 65 फीसदी जूता खपत एवं लगभग 25 फीसदी निर्यात में सहयोग देने वाले छोटे कारीगरों को सहयोग देने की खातिर यह घोषणा शुक्रवार को सर्किट हाउस में ओडीओपी की बैठक में की गई। क्योंकि पीएम मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यह घोषणा करने वाले प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री चौ. उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल और विशेष सचिव गौरव दयाल का कहना है कि छोटे उद्योगों के दम पर ही यह लक्ष्य पूरा होगा।

जमीन की पेशकशः प्रमुख सचिव ने कहा कि एक्सप्रेसवे के पास 20 हेक्टेयर जमीन पड़ी है। यदि चाहें तो वहां स्टोन एवं मार्बिल हैंडीक्राफ्ट का हब बनाया जा सकता है। एक्सप्रेस वे से आने वाले लोग यहां एक ही जगह पर चीजें खरीद पाएंगे।

शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक करते एमएसएमई राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, विशेष सचिव गौरव दयाल, डीएम एनजी रवि कुमार व अन्य। • हिन्दुस्तान

परेशानी सुनी

उप आयुक्त उद्योग शरद टंडन ने बताया कि प्रदेश सरकार की अहम एक जनपद एक उत्पाद योजना को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जगह जगह मीटिंग आयोजित की जा रही हैं। चयनित उत्पाद के समक्ष आ रही दिक्कतों के साथ ही क्षेत्र के दूसरे अन्य उत्पाद के स्टेकहोल्डरों से विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के स्टोन एवं मार्बिल हैंडीक्राफ्ट के उद्यमियो से बातचीत की गई। उनकी दिक्कतों को सुना गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति रही।

मंत्री ने पढ़ाया पाठ

एमएसएमई मंत्री ने बैठक के दस बजे की बजाए एक बजे शुरू होने को लेकर समय प्रबंधन का पाठ पढ़ाया। बोले वे तो इस बैठक के लिए साफा पहन कर, तिलक लगा कर सुबह साढे नौ बजे से ही तैयार हैं। पता चला कि अधिकारी ही नहीं आए हैं। आगाह किया कि भविष्य में यह लेट लतीफी न हो।

केले बेच रहे उस्ताद

एक उद्यमी ने प्रमुख सचिव से कहा कि 60 हजार कारीगर पच्चीकारी से जुड़े हैं। दो साल से काम ठप है। कारीगरों को केले बेचकर, सब्जी के ठेल लगाकर गुजारा करना पड रहा है। दुनिया में केवल आगरा में ही मार्बल पच्चीकारी की कला है, जिसे ट्रेनिंग और वित्तीय मदद देकर बचा सकते हैं।

1.58 करोड़ का चेक दिया

आयोजन के दौरान एसाइड योजना के प्रोजेक्ट ट्रेड सेंटर, टेस्टिंग लैब में प्रदेश सरकार के सहयोग की राशि का 1.58 करोड़ का चेक प्रदान किया गया। एफमक के अनुसार अभी भी काफी राशि मिलना शेष है।

भ्रांतियां दूर हों

स्टोन एवं मार्बिल हस्तशिल्प सेक्टर की जीएसटी एचएसएन कोड की दिक्कत, सब्सिडी मिलने में दिक्कत, कुशलता की कमी आदि को प्रमुख सचिव ने पूरे धैर्य के साथ सुना। बोले, पहले तो सभी सेक्टरों को एक साथ विलय कर स्टोन एंड मार्बिल हैंडीक्राफ्ट नाम रख दिया जाए। उद्यमियो और अवार्डी शिल्पियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और मार्केट बना सकते हैं।

रखी गई यह दिक्कतें

- जूता दस्तकारों के समक्ष सही दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता की दिक्कत। तैयार माल को बेचने की दिक्कत
- आगरा में एड हॉक मोरेटोरियम लगा होने के कारण ओडीओपी योजना कारगर भूमिका में नहीं आ पा रही है।
- जूता उद्योग का कच्चा माल 18 फीसदी टैक्स पर और एक हजार रुपये तक का तैयार माल पांच फीसदी टैक्स पर
- मेगा लेदर पार्क की कमजोर पैरवी के कारण यह प्रोजेक्ट लटका, जूता इकाइयों का विस्तार रुका, नुकसान
- श्रम विभाग के नियमों के कारण कला के पिता से पुत्र को हस्तांतरण में बाधा की समस्या को दूर कराया जाए
- लोन आवेदकों को बैंक टरका देते हैं। राशि बड़ी हो तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। कहां से हो कारोबार
- स्टोन एवं मार्बिल हस्तशिल्प पर टैक्स की दर 12 फीसदी है। जबकि पहले यह कर मुक्त था। कारोबार ठप
- विदेशी खरीदारों के समक्ष आईटीसी रिटर्न की समस्या होने के कारण बिक्री में बड़ी गिरावट हो चुकी है

प्रमुख सचिव के आश्वासन

- डीएम से कहा, कमेटी बनाकर जूता मंडी की दुकानों की सही रेट तय करें। जरूरत पड़े तो शासन से मदद होगी .
- मौके से ही पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी को कॉल किया। वास्तविक दिक्कत सॉल्यूशन पर रिसर्च कराएंगे
- जीएसटी परिषद को पत्र लिख कर समस्या को रखा जाएगा। कच्चे माल के साथ तैयार जूते की दिक्कत दूर होगी
- यूपीएसआईडीसी के शीर्ष अधिकारी को कॉल कर फाइल निकलवाई। मजबूत पैरवी के लिए काम किया जाएगा।
- इंडस्ट्री के सुझाव पर सरकार तैयार। मसौदा पेश करें। एसपीवी बनाएं, दस फीसदी लगाएं, 90 फीसदी सरकार से लें।
- उद्योग विभाग को दी लोन आवेदन की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी। फिर भी दिक्कत तो आरबीआई से करेंगे शिकायत
- जीएसटी परिषद को लिख कर इस समस्या का हल कराने के लिए कहेंगे। सरकार की तरफ से दमदार पैरवी होगी
- इस मामले में भी जीएसटी परिषद से वैकल्पिक व्यवस्था मानने के लिए कहा जाएगा। यह कार्य तुरंत किया जाएगा।

यह दिए गए सुझाव

- एक अरसे से पचकुइया स्थित मंडी बदहाल है। वीरान पड़ी है। दुकानें बाजार दर पर मिलें तो आबाद हो जाएगी
- आगरा के फुटवियर उत्पादन की श्रेणी बदल कर व्हाइट में ले जाना ताकि एडहॉक मोरेटोरियम से फर्क न पड़े
- कच्चे माल पर टैक्स की दर को पांच फीसदी लाया जाए। एक हजार रूपये से ऊपर के जूते को भी पांच फीसदी में
- सीकरी रोड के मेगा लेदर प्रोजेक्ट की दमदार पैरवी की जाए। क्योंकि इसमें पर्यावरण का कोई उल्लंघन नहीं है
- पाठ्यक्रम का हिस्सा बने ओडीओपी। ताकि बच्चों को सातवीं-आठवीं क्लास से ही रोजगार की तरफ जोड़ा जाए
- एससी/एसटी हब की तर्ज पर सरकार गारंटी ले और छोटे उद्यमियों को आसान शर्त पर लोन दिलाया जाए
- स्टोन एवं मार्बिल हस्तशिल्प को कर मुक्त किया जाए। या फिर इसे न्यूनतम टैक्स के स्लैब में लाया जाए
- विदेशी खरीदारों को जब तक एयरपोर्ट पर रिफंड की व्यवस्था नहीं है, तब तक खरीद में राहत दी जाए

Scanned by CamScanner

हस्तशिल्पी बनाएं सीएफसी, मिलेगा अनुदान

एक जिला एक उत्पाद योजना की सर्किट हाउस में वर्कशॉप, मार्बल इनले वर्क को ओडीओपी में शामिल करने की मांग

सर्किट हाउस में एक जिला एक उत्पाद योजना की बैठक लेते एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल, निदेशक एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन गौरव दयाल, डीएम एनजी रवि कुमार, और अन्य • जागरण

जागरण संवाददाता, आगराः शहर का मार्बल इनले वर्क दुनिया भर में अनूठा है। इसे ओडीओपी योजना में सरकार शामिल करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस उद्योग पर संकट है। शुक्रवार को एक जिला एक उत्पाद योजना पर सर्किट हाउस में हुई वर्कशाप में हस्तशिल्पियों ने यह बात उठाई। हस्तशिल्पियों को सुझाव दिया गया कि वह सीएफसी का निर्माण करें, सरकार उन्हें 90 फीसदी अनुदान देगी।

लेदर और मार्बल उत्पाद (ओडीओपी) योजना में ओडीओपी ईको सिस्टम (लेदर व मार्बल इनले) विषय पर इस वर्कशॉप का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने किया। नेशनल चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष राजीव तिवारी ने कहा कि दुनिया में केवल आगरा में ही मार्बल इनले का काम होता है। इसमें करीब 60 हजार कारीगर काम कर रहे हैं। जीएसटी की मार के बाद कारीगर काम छोड़ रहे हैं। इसे ओडीओपी में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। डॉ. एसके त्यागी ने मार्बल इनले के साथ स्टोन हैंडीक्राफ्ट को जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने 12 फीसद जीएसटी पर सवाल उठाए।

प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने कहा कि हस्तशिल्पी सोसायटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन बनाकर कामन फैसिलिटी सेंटर बनाएं। उन्हें 90 फीसद तक अनुदान मिलेगा। सरकार निर्णय लेगी तो ओडीओपी में मार्बल इनले को शामिल किया जाएगा। इससे पूर्व एमएसएमई मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि उद्यमियों को हरसंभव मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास कर रही है। आगरा जूते के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पत्थर और पच्चीकारी के काम से भी इसकी पहचान मुगल काल से है।

केले बेच रहे हैं हस्तशिल्पीः उद्यमी अशोक ओसवाल ने कहा कि हस्तशिल्पी केले बेचने को मजबूर हैं। स्टोन और मार्बल हैंडीक्राफ्ट को जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट पर पर्यटकों को जीएसटी रिटर्न का सिस्टम शुरू नहीं हो सका है। भारतीय पर्यटक जीएसटी की मार नहीं सह पा रहे हैं। रिफंड नहीं मिलने से पैसा फंसा हुआ है।

एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य

प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य प्रदेश में एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का है। जीडीपी बढ़ाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का बड़ा योगदान है। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में प्रदेश भर में आ रही परेशानियों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। हर जिले में एक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगरा में आइएलएस को यह जिम्मा सौंपा गया है। हितधारकों से विचार-विमर्श कर कार्य योजना बनाई जाएगी। पिछले वर्ष निर्यात में 28 फीसद वृद्धि हुई थी। इसमें लेदर प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है।

जूता मंडी की दुकानों की फिर तय होगी कीमत

- प्रमुख सचिव एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन ने दिए निर्देश
- लागत अधिक होने पर ओडीओपी में सरकार देगी अनुदान

जागरण संवाददाता, आगराः एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की वर्कशॉप में जूता दस्तकारों ने जूता मंडी की दुकानों की कीमत अधिक होने का मुद्दा उठाया। प्रमुख सचिव एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने दुकानों की कीमत फिर तय करने के निर्देश डीएम एनजी रवि कुमार व एडीए के अधिकारियों को दिए।

सर्किट हाउस में वर्कशॉप में जूता कारोबारियों ने जूता मंडी की दुकानों की कीमत कम करने की मांग उठाई। इस पर प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने कहा कि दुकानों की लागत का आगणन कराया जाए। मौजूदा रेट से लागत कम है तो दुकानों की कीमत कम कर दें। कीमत अधिक है तो हमें प्रस्ताव भेज दें। ओडीओपी योजना में हम दुकान लेने वाले कारोबारियों को अनुदान देंगे। उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से यह अनुदान मिलेगा। जूता मंडी में करीब 250 दुकानें बनी हुई हैं। अधिक कीमत के चलते उनकी बिक्री नहीं हो सकी है और अधिकांश दुकानें खाली पड़ी हैं। वर्कशॉप में निदेशक एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन गौरव दयाल, डीएम एनजी रवि कुमार, सीडीओ जे. रीभा, एडीएम प्रोटोकॉल मंजूलता, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अंजू रानी, पूरन डाबर, गोपाल गुप्ता, भरत सिंह पिप्पल आदि मौजूद रहे।

प्रशिक्षण को उपलब्ध कराएं सूचीः प्रमुख सचिव ने प्रशिक्षण के लिए इच्छुक व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। उन्हें शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे, जिससे स्किल्ड लेबर की समस्या नहीं हो। प्रशिक्षण के बाद स्वयं का कारोबार करने के इच्छुक व्यक्तियों को उन्होंने मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऋण दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में बैंकों द्वारा ऋण नहीं देने का मुद्दा उठने पर उन्होंने आनाकानी करने वाले बैंकों के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश डीएम एनजी रवि कुमार को दिए।

एक जिला उत्पाद योजना की शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई वर्कशॉप के दौरान एफमेक अध्यक्ष पूरन डाबर को चेक सौंपते एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल। साथ हैं निदेशक एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन गौरव दयाल और अन्य •

12 फीसद से अधिक जीएसटी न रखने की मांग

जूता दस्तकार फेडरेशन के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल ने जूते के कंपोनेंट्स पर 12 फीसद जीएसटी और फाइनल प्रोडक्ट्स पर पांच फीसद ही जीएसटी होने के मुद्दे को रखा। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने जूते पर जीएसटी 12 फीसद से अधिक नहीं लगाए जाने की मांग उठाई।

दोबारा चालू हो लेम्को

जूता कारोबारियों ने वर्कशॉप में वर्ष 2000 से बंद लेम्को को दोबारा शुरू कराने की मांग उठाई। वर्ष 1974 से 2000 तक लेम्को जब चालू थी तब आगरा के कारोबारियों द्वारा पुलिस, पीएससी और सेना के लिए जूते बनाए जाते थे। एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने इसे प्राथमिकता से देखने को कहा।

लेदर पार्क का उठा मुद्दा

लेदर पार्क का मुद्दा भी जूता कारोबारियों ने उठाया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दों में अपना पक्ष रखने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगाई गई तदर्थ रोक को हटवाने के मामले को देखने की बात कही।

लैब के लिए एफमेक को दिया 1.58 करोड़ रुपये का चेक

राज्य मंत्री चौ. उदयभान सिंह और प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर (एफमेक) के अध्यक्ष पूरन डाबर को 1.58 करोड़ रुपये का चेक दिया। सींगना स्थित ट्रेड सेंटर में एफमेक द्वारा टेस्टिंग लैब व डिजाइन स्टूडियो बनाया जा रहा है। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल बैठक के बाद निरीक्षण के लिए सींगना गए।

ग्लू से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को होगा अध्ययन

वर्कशॉप में जूता उद्यमियों द्वारा जूते को ग्रीन से व्हाइट कैटेगरी में कराने की मांग की गई। प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन यादव को रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उद्योगों की कैटेगरी का हवाला दिया। इस पर प्रमुख सचिव ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी से फोन पर वार्ता की। ग्लू व्हाइट कैटेगरी में नहीं है। इस पर प्रमुख सचिव ने जूता इंडस्ट्री में ग्लू के प्रयोग और पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन कराने को कहा।

Shot on OnePlus

एक जिला एक उत्पाद योजना की सर्किट हाउस में

सर्किट हाउस में एक जिला एक उत्पाद योजना की बैठक लेते एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन नवनीत सहगल, निदेशक एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन गौरव दयाल, डीएम एनजी रवि कुमार, और अन्य • जागरण

जाग
एक
वर्क
की
मुद्दा
निर्यात
की व
एनजी
को वि
स

'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) योजनान्तर्गत
एक दिवसीय वर्कशाप का आयोजन
ODOP Ecosystem (लैदर तथा मार्बल इनले) के अध्ययन
में किये जा रहे सर्वे के सम्बन्ध में स्टेकहोल्डर्स से चर्चा
मुख्य अतिथि - श्री चौ. उदयभान सिंह जी
डा. नवनीत सहगल (IAS)
आगरा

Shot on OnePlus
By SS